भारत – नार्वे संबंध

1. राजनीतिक :

21 फरवरी, 1947 को पहले आधिकारिक संपर्क से लेकर स्टाकहोम में भारत के विशेष दूत वी के कृष्णा मेनन को विदेश मंत्री श्री हालवार्ड लांगे की ओर से एक टेलिग्राफिक संदेश जिसमें पुष्टि की गई कि नार्वे सरकार द्विपक्षीय संबंध स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमत है, भारत और नार्वे के बीच मधुर एवं मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। दोनों देश साझे सामान्य मूल्यों जैसे कि लोकतंत्र, मानवाधिकार और कानून का शासन आदि के लिए एक – दूसरे का सम्मान करते हैं। हाल के वर्षों में दोनों देश अपनी – अपनी द्विपक्षीय आर्थिक एवं तकनीकी संपूरकताओं का अधिकाधिक उपयोग कर रहे हैं।

भारत – नार्वे द्विपक्षीय संबंध की खासियत यह है कि दोनों देशों के बीच उच्च स्तर पर यात्राओं का आदान – प्रदान नियमित रूप से होता है। राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने 12 से 14 अक्टूबर, 2014 के दौरान नार्वे का राजकीय दौरा किया जो भारत की ओर नार्वे की पहली राजकीय यात्रा थी। भारत की ओर से नार्वे की मंत्री स्तर पर भी अनेक यात्राएं हुई हैं जिसमें तत्कालीन वित्त मंत्री श्री पी चिदंबरम की अक्टूबर, 2007 में नार्वे यात्रा; भारत - नार्वे संयुक्त आयोग की तीसरी बैठक में शामिल होने के लिए जून 2008 में विदेश राज्य मंत्री श्री आनंद शर्मा की नार्वे यात्रा। मानव संसाधन विकास मंत्री श्री कपिल सिब्बल की जुलाई, 2008 में नार्वे यात्रा; विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री श्री पृथ्वीराज च्वहाण की जून, 2010 में नार्वे यात्रा; ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री डा. सी पी जोशी की सितंबर, 2010 में नार्वे यात्रा; पृथ्वी विज्ञान, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा संसदीय कार्य मंत्री श्री पवन कुमार बंसल की मई, 2011 में नार्वे यात्रा; पोत परिवहन मंत्री श्री जी के वासन की मई, 2011 में नार्वे यात्रा; रक्षा राज्य मंत्री श्री पल्लम राजू की सितंबर, 2011 में नार्वे यात्रा और नवीव एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री डा. फारूख अब्दुल्ला की अक्टूबर, 2011 में नार्वे यात्रा शामिल हैं। पंचायती राज ग्रामीण विकास मंत्री श्री किशोर चंद्र देव ने स्थानीय अभिशासन पर दोनों देशों के बीच हस्ताक्षरित एम ओ यू के अनुवर्तन के रूप में सितंबर, 2012 में नार्वे का दौरा किया; योजना आयोग के सदस्य श्री बी के चतुर्वेदी ने अप्रैल, 2013 में ऊर्जा एवं 2015 पश्चात एजेंडा पर एक उच्च स्तरीय बैठक में भाग लेने के लिए ओस्लो का दौरा किया; पर्यावरण एवं वन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती जयंती नटराजन ने जैव विविधता एवं सी ओ पी ब्यूरो बैठक के सातवें ट्रोंडहेम सम्मेलन में भाग लेने के लिए मई, 2013 में नार्वे का दौरा किया; विदेश मंत्री श्री सलमान खुर्शीद ने जून, 2013 में ट्रोम्सो, स्वालबर्ड एवं ओस्लो का दौरा किया; मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री वी एस संपत ने नार्वे के संसदीय चुनावों को देखने के लिए दिसंबर, 2013 में नार्वे का दौरा किया।

नार्वे की ओर से यात्राएं : नार्वे की ओर से जो यात्राएं हुई हैं उनमें निम्नलिखित शामिल हैं : नार्वे के प्रधानमंत्री श्री जेन्स स्टोलटेनबर्ग ने दिल्ली संपोषणीय विकास शिखर बैठक (डी एस डी एस) के लिए फरवरी, 2010 में भारत का दौरा किया; कृषि एवं खाद्य मंत्री श्री लार्स पेडरब्रेक ने फरवरी, 2010 में भारत का दौरा किया; विदेश मंत्री जुनास गेहरस्टोर ने भारत – नार्वे संयुक्त आयोग की बैठक की सह-अध्यक्षता करने के लिए मार्च, 2010 में भारत का दौरा किया; पर्यावरण एवं अंतर्राष्ट्रीय विकास मंत्री श्री एरिक सोलहेम ने मार्च, 2010, नवंबर, 2010 और फरवरी, 2012 में भारत का दौरा किया; व्यापार एवं निवेश मंत्री

श्री ट्रोंड गिस्के ने अक्टूबर, 2010 और मई, 2012 में भारत का दौरा किया; उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान मंत्री सुश्री टोरा आस्लैंड ने फरवरी, 2011 में भारत का दौरा किया; स्थानीय शासन एवं क्षेत्रीय विकास मंत्री लिव सिग्ने नावार्सेटे ने जनवरी, 2012 में भारत का दौरा किया; सरकारी प्रशासन, सुधार एवं गिरजाघर मंत्री सुश्री रिगमोर अस्रूड ने फरवरी, 2012 में भारत का दौरा किया; कृषि मंत्री श्री ट्राइग्वे एस वेडुम ने अगस्त, 2012 में भारत का दौरा किया; अंतर्राष्ट्रीय विकास उप मंत्री श्री अरविन गाडगिल ने डी एस डी एस के लिए जनवरी – फरवरी, 2013 में भारत का दौरा किया; विदेश मंत्री बोर्ग ब्रेनडिंग ने 11वीं असेम विदेश मंत्री बैठक के लिए नवंबर, 2013 में भारत का दौरा किया, रक्षा मंत्रालय में राज्य सचिव ओइस्टीन बो ने दिसंबर, 2013 में भारत का दौरा किया और अप्रैल 2015 में नार्वे - एशिया व्यवसाय शिखर बैठक में भाग लेने के लिए यूरोपीय मामले मंत्री श्री विडार हेल्गीसन तथा नार्वे के प्रधानमंत्री के चीफ ऑफ स्टाफ एवं राज्य सचिव मार्टेन होगलुंड ने भारत का दौरा किया। फरवरी 2015 में व्यवसाय एवं उद्योग संबंधी स्थाई समिति के अध्यक्ष श्री गीर पोलेसैंड के नेतृत्व में स्टोर्टिंग (संसद) से 12 संसद सदस्यों ने भारत का दौरा किया। नार्वे के विदेश मंत्री श्री बोर्ज ब्रेंडे ने 2 एवं 3 नवंबर 2015 नई दिल्ली में आयोजित संयुक्त समिति की 5वीं बैठक के लिए भारत का दौरा किया।

भारत – नार्वे संयुक्त आयोग की बैठकों का आयोजन संबंधित विदेश मंत्रियों की अध्यक्षता में होता है। भारत - नार्वे संयुक्त आयोग की 5वीं बैठक 2 नवंबर, 2015 को नई दिल्ली में हुई।

दोनों देशों के विदेश मंत्रालयों के बीच विदेश कार्यालय परामर्श का आयोजन वार्षिक आधार पर विदेश सचिवों के स्तर पर वैकल्पिक रूप में नई दिल्ली और ओस्लो में होता है। नवंबर, 2013 में, नई दिल्ली में क्षेत्रीय कार्य एवं विकास विभाग में महानिदेशक श्री टोरे हट्टरेम ने संयुक्त सचिव (सी ई) के साथ विदेश कार्यालय परामर्श किया। सचिव (पश्चिम) श्री दिनकर खुल्लर ने अप्रैल, 2014 में ओस्लो में नार्वे के विदेश मंत्रालय में उप राज्य सचिव श्री क्रिस्टियन सायसे के साथ विदेश कार्यालय परामर्श का आयोजन किया।

नार्वे के विदेश कार्यालय में यूएन विभाग के महानिदेशक ने जनवरी, 2014 में नई दिल्ली में अपर सचिव (आई ओ) के साथ पहले आधिकारिक यूएन परामर्श का आयोजन किया। दूसरे चक्र का आयोजन मई 2015 में ओस्लो में हुआ।

नार्वे ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थाई सीट के लिए भारत की उम्मीदवारी के लिए अपना समर्थन प्रदान किया है। इसने 2011-12 की अवधि के लिए सुरक्षा परिषद में अस्थाई सीट के लिए भारत की उम्मीदवारी के लिए भी अपना समर्थन प्रदान किया था।

संयुक्त कार्य समूह : भारत – नार्वे संयुक्त आयोग के तत्वावधान में अनेक संयुक्त कार्य समूह (जे डब्ल्यू सी) का गठन किया गया है जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं : (i) पर्यावरण पर संयुक्त कार्य समूह; (ii) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर संयुक्त कार्य समूह; (iii) उच्च शिक्षा पर संयुक्त कार्य समूह; (iv) हाइड्रो कार्बन पर संयुक्त कार्य समूह; (v) संस्कृति पर संयुक्त कार्य समूह; (vi) स्थानीय अभिशासन पर परस्पर सहयोग के लिए संयुक्त कार्य समूह; (vii) समुद्री मामलों पर संयुक्त कार्य समूह; और (viii) मछली पालन पर

संयुक्त कार्य समूह। संगत क्षेत्रों में परस्पर लाभप्रद मुद्दों पर विचार – विमर्श के लिए संयुक्त कार्य समूहों की नियमित रूप से बैठक होती है।

करार एवं एमओयू : दोनों देशों के बीच निम्नलिखित करारों एवं एम ओ यू पर हस्ताक्षर किए गए हैं :

क्र. सं.	करार
1	1986 में दोहरा कराधान परिहार करार (डी टी ए ए); संशोधित डी टी ए ए पर हस्ताक्षर फरवरी, 2011 में किया गया
2	हवाई सेवा करार (जिस पर 1995 में हस्ताक्षर किए गए तथा 2008 में इसके लिए एम ओ यू की पुष्टि की गई)
3	सांस्कृतिक करार (1961)
4	सामाजिक सुरक्षा पर करार (2010)
5	राजनयिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा की आवश्यकता से छूट के लिए करार (अक्टूबर, 2014)

क्र. सं.	एम ओ यू
1	दोनों देशों के विदेश सेवा संस्थानों के बीच एम ओ यू (2005)
2	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए एम ओ यू (2006)
3	नार्वे – भारत साझेदारी पहल (एन आई पी आई) पर एम ओ यू (2006)
4	ध्रुवीय अनुसंधान पर एम ओ यू (2008)
5	शिक्षा एवं अनुसंधान पर एम ओ यू (2008)
6	जलवायु परिवर्तन एवं सी डी एम पर सहयोग के लिए एम ओ यू (2009)
7	मछली पालन में सहयोग के लिए एम ओ यू (2010)
8	स्थानीय अभिशासन पर परस्पर सहयोग के लिए एम ओ यू (2010)
9	बैंकिंग पर्यवेक्षण में सहयोग के लिए आर बी आई तथा नार्वे वित्तीय सेवा प्राधिकरण के बीच एम ओ यू (जुलाई, 2012)
10	भारत के संस्कृति मंत्रालय तथा नार्वे के मुंख संग्रहालय के बीच एम ओ यू (अक्टूबर, 2014)
11	पृथ्वी प्रणाली विज्ञान के क्षेत्र में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय तथा नार्वे की अनुसंधान परिषद के बीच एम ओ यू (अक्टूबर, 2014)
12	आई आई एस ई आर, तिरूवनंतपुरम एवं एस आई एन टी ई एफ सामग्री एवं रसायन शास्त्र के बीच एम

	ओ यू (अक्टूबर, 2014)
13	ओस्लो विश्वविद्यालय तथा हैदराबाद विश्वविद्यालय के बीच एम ओ यू (अक्टूबर, 2014)
14	डी आर डी ओ तथा नार्वे रक्षा अनुसंधान प्रतिष्ठान (एफ एफ आई) के बीच मंशा वक्तव्य (अक्टूबर, 2014)
15	ओस्लो विश्वविद्यालय तथा आई आई टी कानपुर के बीच एम ओ यू (अक्टूबर, 2014)
16	वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद तथा एस आई एन टी ई एफ के बीच एम ओ यू (अक्टूबर, 2014)
17	भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद तथा नार्वे अनुसंधान परिषद के बीच एम ओ यू (अक्टूबर, 2014)
18	आई आई टी कानपुर एवं एन आई एल यू के बीच एम ओ यू
19	हैदराबाद विश्वविद्यालय एवं बर्गेन विश्वविद्यालय के बीच एम ओ यू (अक्टूबर, 2014)
20	हैदराबाद विश्वविद्यालय एवं एन टी एन यू के बीच एम ओ यू (अक्टूबर, 2014)
21	अगडेर विश्वविद्यालय तथा इंदिरा गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय के बीच एम ओ यू (अक्टूबर, 2014)

2010 से 2015 की अवधि के लिए भारत और नार्वे के बीच सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम पर हस्ताक्षर मई, 2010 में ओस्लो में किया गया। 2010 में हस्ताक्षरित सामाजिक सुरक्षा करार 01 जनवरी, 2015 को प्रभावी हुआ।

वार्ता के अधीन करार / एम ओ यू : इस समय निम्नलिखित करार / एम ओ यू वार्ता के अधीन हैं : (i) आपराधिक मामलों में परस्पर कानूनी सहायता संधि (ii) भारत एवं ई एफ टी ए (आइसलैंड, नार्वे, लिचिस्टीन, स्वीटजरलैंड) के बीच व्यापार एवं निवेश करार;

2. □□□□□□□□□□

□□□□□□□□ : □□□□□□□ □□ □□ □□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□□□□□□□□ □□□□, □□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□, □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□, □□□□□□□□ □□□□□□, □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□, □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□, □□□□□ □□□□□ □□ □□ □□ □□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□, □□□□□□□, □□□□□ □□□□□□ □□□□

□□□□□□□□, □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□, □□□□□, □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□, □□□□□ □□□□□□□, □□□□□, □□□□□□□□, □□□□□□□ □□□□□□, □□□□□□ □□ □□□□□□□□, □□□□□, □□□, □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□

□□□ □□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□, □□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□, □□□□□□□□□ □□□□□□, □□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□ 2013-2014 □□□□ 974.22 □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□, □□□□□ 2014-2015 □□□□ □□□□□□ 1,264.52 □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□ (□□□□□□ : □□□□□□□□ □□□□□□□□□□, □□□□□ □□□□□□, □□□□□)

निवेश : नार्वे की लगभग 90 कंपनियां या तो भारतीय साझेदारों के साथ संयुक्त उद्यम के माध्यम से या फिर पूर्णता स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों के माध्यम से भारत में सक्रिय हैं। नार्वे की 100 से अधिक कंपनियों ने पोत निर्माण, पेट्रोलियम से संबंधित सेवा, समुद्री / समुद्र के अंदर ड्रिलिंग उपकरण, जल विद्युत, स्वच्छ ऊर्जा तथा आईटी सेवा जैसे क्षेत्रों में कारोबार की संभावनाओं में अपनी रूचि का प्रदर्शन किया है। रिलायंस इंडस्ट्री तथा ओ एन जी सी ने पेट्रोलियम तथा ऊर्जा क्षेत्र में नार्वे की कंपनियों के साथ अनुबंध किया है। नार्वे की आई टी कंपनियों में भारत में अपने कारोबार को स्थापित करने या भारतीय कंपनियों में शेयर प्राप्त करने में भी प्रगति है।

समुद्री प्रचालन में नार्वे की विशेषज्ञता की भारत में मांग है तथा इसी तरह नार्वे के पोत परिवहन उद्योग ने भारतीय शिप यार्ड में पोत बनाने की संभावना एवं आर्थिक व्यवहार्यता का पता लगाया है। 30 से अधिक पोत निर्माण के अधीन हैं जिन्हें नार्वे के पोत स्वामियों के आदेश पर भारतीय शिपयार्ड से निर्मित या डिलीवर किया जा रहा है। नार्वे की सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी टेलीनॉर भारतीय मोबाइल आपरेटर यूनीनॉर में 50 प्रतिशत से अधिक शेयर का स्वामी है। यूनिटेक वायरलेस के साथ अपने अनुबंध को अलग करने के बाद टेलेनॉर ने मैसर्स लक्षद्वीप इंवेस्टमेंट के साथ संयुक्त उद्यम में पूर्णत: स्वामित्व वाली अपनी सहायक कंपनी टेलीर्विंग्स कम्युनिकेंशंस के माध्यम से 1200 मिलियन अमरीकी डॉलर का निवेश किया है। भारत में नार्वे के अन्य प्रमुख निवेशकों में निम्नलिखित शामिल हैं : (i) एस एन पावर जिसने हिमाचल प्रदेश में स्टेटक्राफ्ट एण्ड नोरफंड द्वारा वित्त पोषित 2 जल विद्युत परियोजनाओं में लगभग 270 मिलियन अमरीकी डालर का निवेश किया है और (ii) नार्वे का सबसे बड़ा संयंत्र विनिर्माता - जोटुन जिसने लगभग 60 मिलियन अमरीकी डालर का निवेश किया है। नार्वे के सबसे बड़े बैंक डीएनबी नॉर ने फरवरी, 2009 में मुंबई में अपना प्रतिनिधि कार्यालय खोला है।

आईटी क्षेत्र की भारत की प्रमुख कंपनियों जैसे कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इंफोसिस, एच सी एल, लार्सन एंड टुब्रो इंफोटेक कॉग्निजांट तथा टेक महिंद्रा ने पिछले कुछ वर्षों में इस देश में आईटी आउटसोर्सिंग संविदाओं की विद्यमान संभावना को देखते हुए नार्वे में अपनी उपस्थिति बढ़ाई है।

पिछले कुछ वर्षों में नार्वे में भारतीय कंपनियों ने भी निवेश किया है। सबसे बड़े निवेशों में से एक चेन्नई आधारित अबान ऑफशोर द्वारा निवेश है जिसने लगभग 1.3 बिलियन अमरीकी डालर मूल्य के एक सौदे के तहत वर्ष 2007 के पूर्वार्ध में नार्वे की ड्रिलिंग कंपनी सिनवेस्ट का अधिग्रहण किया। चेन्नई आधारित एक अन्य कंपनी – सिवा वेंचर्स ने नार्वे की जहाजरानी कंपनी जे बी ऊग्लैंड शिपिंग एएस का अधिग्रहण 2008 में 300 मिलियन अमरीकी डालर के बदले में किया; इसने 2010 में नार्वे की बोतल बंद पानी बनाने वाली कंपनी इस्कलार एएस का भी अधिग्रहण किया। टाटा मोटर्स ने नार्वे की कंपनी मिल्जो ग्रेनलैंड / इन्नोवासजोन में 50.3 प्रतिशत शेयर की खरीद की है, जिसका इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए हाइटेक बैटरी विकसित करने में विशेषाधिकार है।

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश : अप्रैल 2000 से मई 2015 के दौरान आर बी आई / एफ आई पी बी के माध्यम से नार्वे से एफ डी आई अंत:प्रवाह 934.54 करोड़ रुपए (लगभग 180 बिलियन अमरीकी डालर) के आसपास था। भारत में 0.07 प्रतिशत के कुल संचयी अंत:प्रवाह के साथ नार्वे 37वें स्थान पर है। सर्वोच्च एफ डी आई इक्विटी अंत:प्रवाह रसायन (उर्वरकों से भिन्न) क्षेत्र में है जो 40 प्रतिशत से अधिक है तथा इसके बाद पुस्तक मुद्रण (जिसमें लीथो प्रिंटिंग उद्योग शामिल है) का स्थान है जो 13 प्रतिशत से अधिक है, व्यापार में निवेश 10 प्रतिशत से अधिक है, सेवा क्षेत्र में 6 प्रतिशत और विद्युत उपकरण में निवेश 4 प्रतिशत है।

जी पी एफ जी : 2014 में नार्वे के गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल (जी पी एफ जी) का बाजार मूल्य अनुमानित तौर पर 6431 बिलियन नार्वेजियाई क्रोनर (एन ओ के) (लगभग 1020.8 बिलियन अमरीकी डालर) था, जिसकी वजह से यह यूरोप में सबसे बड़ा और पूरी दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा पेंशन फंड है। पिछले तीन वर्षों में नार्वे सरकार ने भारत में जी पी एफ जी से निवेश में काफी वृद्धि करने के लिए नीतिगत पहलें की है जो तकरीबन 9 बिलियन अमरीकी डालर है। इस समय ये मुख्य रूप से इक्विटी (58.4 प्रतिशत) तथा फिक्स्ड इनकम बॉन्ड (41.6 प्रतिशत) में हैं। *(स्रोत : नोर्गेस बैंक इनवेस्टमेंट मैनेजमेंट, दिनांक 13 मार्च 2015)*।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी : मई, 2009 में, ओस्लो में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर गठित संयुक्त आयोग की दूसरी बैठक के दौरान दोनों पक्षों द्वारा एक सहयोग कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किया गया। भारत की ओर से अब तक तीन आर्कटिक मिशनों ने 2007, 2008 और 2009 में नार्वे का दौरा किया है। भारत के ध्रुव अनुसंधान केंद्र हिमाद्रि का उद्घाटन जुलाई, 2008 में स्वालबर्ड में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री कपिल सिब्बल द्वारा किया गया। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री पृथ्वीराज च्वहाण द्वारा भी जून,

2010 में इस अनुसंधान केंद्र का दौरा किया गया तथा उनके उत्तराधिकारी श्री पवन कुमार बंसल ने मई, 2011 में इसका दौरा किया। विदेश मंत्री श्री सलमान खुर्शीद ने जून, 2013 में हिमाद्रि अनुसंधान केंद्र का दौरा किया। अप्रैल से अक्टूबर के दौरान हर साल अनुसंधान करने के लिए हमारे शोध वैज्ञानिकों की टीमों द्वारा नियमित आधार पर इस केंद्र का दौरा किया जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर भारत – नार्वे जे डब्ल्यू जी की तीसरी बैठक अक्टूबर, 2012 में बर्गेन, नार्वे में हुई। संयुक्त कार्य समूह की बैठक के दौरान 2012 से 2015 की अवधि के लिए एक सहयोग कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किया गया।

स्वास्थ्य : शिशु मृत्यु दर कम करने तथा मातृत्व स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए सहस्राब्दी विकास लक्ष्य 4 एवं 5 को प्राप्त करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता के अनुसरण में नार्वे सरकार नार्वे – भारत साझेदारी पहल के अंग के रूप में 2006 से 2011 की अवधि में 80 मिलियन अमरीकी डालर की राशि से भारत के राज्यों में कार्यक्रमों का समर्थन कर रही है। अलग से, द्विपक्षीय जैव प्रौद्योगिकी सहयोग के तहत नार्वे मानव वैक्सीन अनुसंधान के लिए 50 मिलियन एन ओ के तथा पशु एवं मछली वैक्सीन अनुसंधान के लिए 15 मिलियन एन ओ के प्रदान कर रहा है।

3. सांस्कृतिक संबंध :

नोबल शांति पुरस्कार : नार्वे की नोबल समिति द्वारा 10 दिसंबर, 2014 को ओस्लो में "बच्चों एवं युवाओं के दमन तथा सभी बच्चों के शिक्षा के अधिकार के लिए संघर्ष" के लिए 2014 का नोबल शांति पुरस्कार भारत के बाल अधिकार कार्यकर्ता श्री कैलाश सत्यार्थी को (संयुक्त रूप से पाकिस्तान की मलाला युसुफजई के साथ) प्रदान किया गया।

□□□□□□□□□□□□□□□ □□□ □□□□ □□□□□□ (21 □□□, 2015) : 21 □□□ 2015 □□ □□□□□ □□□ □□□□□□□□□□□□□□□ □□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ 1500 □□□□□ □□ □□ □□□□□□□□□ □□□ □□□ □□□□ □□□□□□ □□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□, □□□□□ □□□□□□□□□, □□□□□□□, □□□ □□□□□□□□ □□□ □□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□ □□ □□□ □□□□□□□□□ □□□ □□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□ □□ □□□ □□□□□ □□□□

4. भारतीय समुदाय

जनवरी, 2014 तक की स्थिति के अनुसार नार्वे में भारतीय समुदाय की संख्या 12924 थी, जिसमें से 9485 पी आई ओ कार्ड धारक हैं तथा 3439 एन आर आई हैं। नार्वे में रहने वाले अधिकांश भारतीय

पेशेवर हैं तथा अपने – अपने क्षेत्रों में बहुत ही सफल हैं। नार्वे के उत्प्रवास विभाग के आंकड़ों के अनुसार भारत नार्वे में काम करने वाले विदेशी कुशल पेशेवरों का अग्रणी स्रो बन गया है। भारत से कुशल पेशेवरों की संख्या वर्ष 2005 में मात्र 100 से बढ़कर 2014 में 2000 के आसपास पहुंच गई है।

वीजा : पर्यटन एवं व्यवसाय के प्रयोजनों के लिए अधिक संख्या में नार्वे के लोग भारत की यात्रा पर आ रहे हैं। 27 नवंबर 2014 से नार्वे के लिए ई-टूरिस्ट वीजा (ई टी वी) लागू किया गया है तथा अब तक 2884 नार्वेजियन ने इस सुविधा का उपयोग किया है।

राजनयिक पासपोर्ट धारकों को अक्टूबर 2014 में द्विपक्षीय करार पर हस्ताक्षर होने के बाद से वीजा की आवश्यकता से छूट है।

उपयोगी संसाधन :

भारतीय दूतावास, ओस्लो की वेबसाइट
www.indemb.no

भारतीय दूतावास, ओस्लो की फेसबुक
https://www.facebook.com/pages/India-in-Norway/410130359164835?ref=hl

भारतीय दूतावास, ओस्लो ट्विटर लिंक :
https://twitter.com/Indemb_Norway

*****

जनवरी, 2016